

HRIVITATIEXTRACEDENARY

भाग I—शण्ड । PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 102] नई बिल्ली, बृहस्पतिवार, सर्वे 14, 1987/वैशास 24, 1909 №. 102] NEW DELHI, THURSDAY. M\Y 14, 1937, V\IS\KH\ 24, 1909

इस भागः में भिन्न पृष्ठ संस्था दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि और न्याय मतालय (विधि कार्य विभाग) नई दिल्ली, 14 मई, 1987

संबल्प

एत, स. 6 (15)/86-का. मे. —केन्द्रीय मरकार, सरकार के तारीख 19 फरवरी, 1987 के समसंख्यांक सकल्प के कम मे, न्यायमूर्ति श्री ग्रार. एस. पाठक, मुख्य न्यायमूर्ति, भारत का उच्चतम न्यायालय और प्रमुख सरक्षक, विधिक सक्तें ।

सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति के घंधीन विधिक सहायता स्कीम कार्याच्यान

- समिति का निम्नलिखित रूप में पनर्गठन करती है :---
 - (1) न्यायमिति श्री रंगनाथ मिश्र, न्यायाधीश, भारत --कार्यपालक प्रध्यक्ष का उच्चतम न्यायालय
 - (2) न्यायमति श्री एन. डी. ओहा, मुख्य न्याय-मिल मध्य प्रवेश उच्च न्यायालय
 - (3) न्यायमृति श्री वी. रन्नम, न्यायाधीण, महाम उच्च न्यायालय ----**मदस्य**
 - (4) मचिव (व्यय), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार --- सदस्य
 - (5) सम्रिव, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय (6) सचिव, विधिक सहायता स्कीम कार्यान्धयन
 - समिति (प्रमुख संरक्षक में परामर्श करके कुछ अन्य मदस्य भी नियक्त किए जा
 - 2. कार्यपालक श्रध्यक्ष और अन्य सदस्य एक वर्ष के लिए पद धारण करेंगे।
 - ं 3. यह सरकार के तारीख 15 ग्रक्तुबर, 1985 के संकल्प सं. एफ. 6(18)/85-का. से. का और उपांतरण करता है।
 - पी, के.क थं अभिव

(Department of Legal Affairs)

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

New Dolhi, the 14th May, 1987

RESOLUTION

No. F. 6(15)/86-IC.—The Contral Government in continuation of the continuation of the contral continuation of the contral continuation of the contral continuation of the contral Resolution of even number dated 19th February, 1987 hereby recognitutes the Committee for Implementing Legal Aid Schemes under Shri Justice R.S. Pathak. Chief Justice Supreme Court of India and Patron-in-Chief. Committee for Implementing Legal Aid Schemes as follows:-

(1) Shri Justice Ranganath Mishra Judge, Supreme Court of India. --- Executive Chairman

- (2) Shri Justice N.D. Ojha, Chief Justice of Madhya

 Pradesh High Court

 Member
- (3) Shri Justice V. 20 Comparish of the Madras High

 Court

 —Member
- (4) Socretary (Appendicate). Ministry of Finance,
 Govt. of 1 c.k.
- (5) Secretary, Department of Legal Affairs, Ministry of Law & Justice —Member
- (6) Secretary, CILAS

 —Member-Secretary

 (A few other Members may be appointed in consultation with the Patrim-in-Chief).
- 2. Executive Chairman and other Members shall hold office for a period of one year.
- 3. This is in further modification of Government Resolution No. £6(18)/85-IC, dated 15th October, 1985.

P.K. KARTHA. Secv.

¥